



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 20, 2017/भाद्र 29, 1939

No. 246]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 20, 2017/BHADRA 29, 1939

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 सितम्बर, 2017

सं. 26/2015-2020

विषय:— प्रक्रिया पुस्तक 2015-20 में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. 01/94/180/172/एम17/पीसी-4.—समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक 2015-2020 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, जो निम्नानुसार है:

1. पैरा 4.06 में संशोधन किया गया है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

4.06 मानदंड निर्धारण

(i) उन मामलों में जहां मानदंड अधिसूचित नहीं किए गए हैं, अथवा जहां आवेदक अग्रिम प्राधिकार पत्र हेतु आवेदन करने से पहले तदर्थ मानदंड निर्धारित कराने का इच्छुक हो सिओन/तदर्थ मानदंड निर्धारण के लिए एएनएफ 4ख में आवेदन निर्धारित दस्तावेज समेत डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति (एनसी) को आनलाइन अपलोड किया जाएगा। प्रत्येक मानदंड समिति द्वारा देखरेख किए जा रहे उत्पाद समूह के साथ मानदंड समितियों और मानदंड निर्धारण से संबंधित पत्राचार हेतु संबंधित ईमेल पता का ब्यौरा निम्नानुसार है:

डीजीएफटी मुख्यालय में मानदंड समिति (एनसी)	निम्नलिखित आईटीसी एचएस अध्यायों के तहत निर्यात उत्पादों के मानदंडों का निर्धारण/परिशोधन/संशोधन	संबंधित मानदंड समिति के साथ सम्पर्क हेतु ईमेल पता
एनसी-1	81 से 84, 86 से 93	nc1.dgft@nic.in
एनसी-2	72 से 76, 78 से 80, 85	nc2.dgft@nic.in
एनसी-3	29, 30	nc3.dgft@nic.in
एनसी-4	27, 28, 31 से 38, 44 से 49, 68 से 71	nc4.dgft@nic.in
एनसी-5	41 से 43, 50 से 67	nc5.dgft@nic.in
एनसी-6	1 से 26, 94 से 98	nc6.dgft@nic.in
एनसी-7	39, 40	nc7.dgft@nic.in

(ii) आवेदक सम्पर्क के लिए वैध ईमेल पता दर्शाएगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि यह ईमेल पता सक्रिय है।

(iii) मानदंड समितियों के निर्णय डीजीएफटी की वेबसाइट (<http://dgft.gov.in>) पर आवधिक रूप से उपलब्ध रहेंगे तथा आवेदक स्वयं को प्राप्त प्राधिकार पत्र के संबंध में मानदंड निर्धारण की स्थिति से स्वयं को अद्यतन करेगा।

(iv) निर्यातक/ईपीसी किसी निर्यात उत्पाद हेतु सिओन/तदर्थ मानदंड निर्धारण के लिए संबंधित मानदंड समिति को आँकड़े उपलब्ध कराएंगे। मानदंड समिति सम्पूर्ण आँकड़े प्राप्त होने पर सिओन अथवा तदर्थ मानदंड निर्धारित करने हेतु प्रयास करेगी। किसी निर्यातक द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर इस पैरा के तहत निर्धारित कोई तदर्थ मानदंड केवल एक प्राधिकार पत्र के लिए वैध होगा जिसके लिए ऐसा आवेदन किया गया है और पुनः कोई अन्य प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया जाएगा। तथापि, मानदंड समिति वैधता अवधि बढ़ाए जाने के संबंध में विशेष रूप से उल्लेख कर सकती है और यह अवधि इस मानदंड के तहत और प्राधिकार-पत्र जारी करने हेतु ऐसे तदर्थ मानदंडों के निर्धारण की तारीख से दो वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(v) मानदंड समितियां सिओन की अधिसूचना के लिए सिफारिशी प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करेंगी तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय समय-समय पर ऐसे मानदंड अधिसूचित कर सकती है।

(vi) उद्योग जगत/विनिर्माताओं/ईपीसी के लिए पिछले तीन वर्षों का उत्पादन एवं खपत आंकड़ा प्रदान करना अनिवार्य है जिसकी सिओन के निर्धारण के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा मांग की जाए। अन्यथा, आवेदकों को स्व-घोषणा आधार पर दुबारा अग्रिम प्राधिकार-पत्र लेने के लिए अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम का लाभ लेने की अनुमति नहीं होगी। मानदंड समिति केन्द्रीय उत्पाद (सीबीईसी) से भी आंकड़े की मांग कर सकती है।

(vii) मानदंडों के निर्धारण हेतु वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय संस्थानों से विशेषज्ञों को मानदंड समिति के सदस्यों के रूप में आमंत्रित किया जा सकता है।

2. पैरा 4.10 में संशोधन किया गया है जिस निम्नानुसार पढ़ा जाएगा;

4.10 एक से अधिक यूनिटों वाले आवेदकों हेतु अग्रिम प्राधिकार पत्र

(i) विनिर्माण प्रयोजन हेतु एक कंपनी की यूनिट से दूसरी कंपनी को अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे आयातित या प्राप्त किसी शुल्क मुक्त माल का हस्तांतरण क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा शुल्क प्राधिकारियों को पूर्व सूचना के साथ किया जाएगा। ऐसी हस्तांतरित निविष्टियों पर कोई सेनवेट लाभ का दावा नहीं किया जाएगा।

(ii) हटा दिया गया है

(iii) हटा दिया गया है

(iv) हटा दिया गया है

(v) आयातित शुल्क मुक्त निविष्टियों को पत्तन/स्वदेशी आपूर्तिकर्ता के परिसर से प्राधिकार पत्र/ सह-प्राधिकार-पत्र

धारक के फैक्टरी या परिसर अथवा सहायक विनिर्माता की फैक्टरी में ले जाया जाएगा (जिनका नाम प्राधिकार पत्र में पृष्ठांकित या क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा अनुमत है)। तथापि, अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे आयातित अथवा खरीदे गए ऐसे शुल्क मुक्त माल को आयात के पत्तन पर सीमाशुल्क प्राधिकारी को बंधपत्र और अन्य दस्तावेज/घोषणा प्रस्तुत करने तथा राजस्व विभाग के दिशा निर्देशों के अनुसार अन्य प्रावधानों के अधीन पत्तन से परियोजना प्राधिकारी की परियोजना साइट तक सीधे ले जाया जा सकता है।

3. पैरा 4.12 (vii) में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

जहां आवेदक ने "जवाबदेही शर्त के साथ निवल दर निवल आधार" पर संघटकों के लिए आवेदन किया है और ऐसे मामले सभी निर्यात उत्पादों के लिए सामान्य टिप्पणी के पैराग्राफ-6 के अन्तर्गत आते हैं तो इन्हें मानदंड निर्धारण के लिए मानदंड समिति के पास भेजने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, निर्यातक निर्यात/आपूर्ति दस्तावेजों जैसे पोतलदान बिल, निर्यात बिल, जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों हेतु कर बीजक में "जवाबदेही शर्त के साथ निवल दर निवल आधार" पर आयातित ऐसी निविष्टियों के ब्यौरे स्पष्ट रूप से दर्शाएंगे जिसमें यह साक्ष्य हो कि इन आयातित निविष्टियों का निर्यात किया गया है।

4. पैरा 4.14 में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

4.14 मानदंड/तदर्थ मानदंड निर्धारण के लिए आवेदन और आनलाइन अन्तर-मंत्रालयी परामर्श

(i) आवेदक द्वारा आनलाइन प्रस्तुत आवेदन को डीजीएफटी मुख्यालय में संबंधित मानदंड समिति द्वारा तीन दिनों के भीतर संबंधित तकनीकी/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक संस्थाओं या किसी अन्य एजेंसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजा जाएगा।

(ii) संबंधित तकनीकी/प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग/वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक संस्थाओं या कोई अन्य एजेंसी, जैसा भी मामला हो, 45 दिनों के भीतर अपने विचार/टिप्पणी/सिफारिश इलेक्ट्रॉनिक रूप से/आनलाइन भेज सकते हैं। यदि 90 दिनों के भीतर कोई टिप्पणी नहीं प्राप्त होती है तो मानदंड समिति रिकार्ड में उपलब्ध तथ्य के आधार पर अपना मत बना सकती है।

5. पैरा 4.16 (iii) में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

पैराग्राफ 4.12 के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र देने हेतु आवेदक की हकदारी अग्रिम प्राधिकार पत्र के तहत आवेदक द्वारा आवेदित निविष्टि की मात्रा कम होने तथा मानदंड समिति द्वारा मानदंडों के निर्धारण से पूर्व पूरे किए गए निर्यात दायित्व के मामलों में, पैराग्राफ 4.12 में यथा-उल्लिखित प्राधिकार पत्र की हकदारी विगत प्राधिकार पत्रों के संबंध में निर्यात दायित्व की पूर्ति दर्शाने वाले दस्तावेजी प्रमाण (शिपिंग बिल/निर्यात बिल की प्रतियाँ/जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित आपूर्ति हेतु कर बीजक) प्रस्तुत करने पर पुनः उनके खाते में डाली जाएगी। तथापि, ऐसे मामलों में मानदंडों के निर्धारित होने तक बांड मुक्त करने/बांड निष्क्रिय करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. पैरा 4.20 में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

उप-पैराग्राफ (च) को छोड़कर प्रक्रिया पुस्तक, 2015-20 के पैराग्राफ 4.49 में उल्लिखित प्रावधान लागू रहेंगे। क्षेत्रीय प्राधिकारी गैर-उल्लंघन प्रक्रिया के द्वारा विनिर्मित भेषज उत्पाद (उत्पादों) के लिए जारी प्रत्येक अग्रिम प्राधिकार पत्र के मद्दे विमुक्ति अथवा बाँड में छूट की अनुमति देने से पहले क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित और प्रमाणित परिशिष्ट-4अ के ब्यौरे से प्राधिकार पत्र में दी गई/अनुमत निविष्टियों के ब्यौरे की तुलना करेगा। सत्यापन प्रक्रिया के फलस्वरूप यदि यह पाया जाता है कि प्राधिकारी पत्र धारक ने आयात की गई मात्रा की तुलना में कम मात्रा की खपत की है तो प्राधिकार पत्र धारक अप्रयुक्त आयातित माल पर राजस्व विभाग द्वारा यथा-अधिसूचित ब्याज सहित सीमा-शुल्क भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा अथवा निर्यात दायित्व अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्यात करेगा। तथापि, सीमा-शुल्क घटक के लिए प्राधिकार पत्र धारक के पास विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के अंतर्गत जारी मान्य ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स प्रस्तुत करने का भी विकल्प होगा।

7. पैरा 4.21 में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

प्रत्येक प्राधिकार पत्र धारक परिशिष्ट 4अ में यथा-निर्धारित प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे शुल्क मुक्त आयातित/स्वदेशी रूप से खरीद की गई निविष्टियों की खपत और उपयोग का सही और उपयुक्त लेखे का रखरखाव करेगा। क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित और प्रमाणित, परिशिष्ट 4अ प्रपत्र में यह रिकार्ड विमुक्ति/बाँड में छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। क्षेत्रीय प्राधिकारी प्रत्येक प्राधिकार पत्र के मद्दे विमुक्ति अथवा बाँड में छूट की अनुमति देने से पहले परिशिष्ट -4अ के ब्यौरे से प्राधिकार पत्र में अनुमत निविष्टियों के ब्यौरे की तुलना करेगा। ऐसे रिकार्डों को विमुक्ति की तारीख से न्यूनतम तीन वर्षों की अवधि के लिए रखा जाएगा।

8. निम्नलिखित उप-पैरा 4.22(ख)(iv) को पैरा 4.22(ख) (iii) के नीचे जोड़ा गया है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा।

(iv) यदि कोई आवेदक किसी निर्धारित दस्तावेज को अपलोड नहीं कर पाता है, तो इन दस्तावेजों को वास्तविक रूप में संबंधित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जा सकता है।

9. पैरा 4.27 और 4.27 (क) के शीर्ष में संशोधन किया गया है, जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

4.27 प्राधिकार पत्र की प्रत्याशा में अथवा प्राधिकार पत्र जारी किए जाने के पश्चात निर्यात/आपूर्ति

(क) अग्रिम प्राधिकार पत्र के लिए ईडीआई द्वारा तैयार फाइल संख्या जारी करने की तारीख से किए गए निर्यात/आपूर्तियों को निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए स्वीकार किया जाएगा। जारी प्राधिकार पत्र के साथ निर्यातों/आपूर्तियों से संबंध स्थापित करने के लिए फाइल संख्या अथवा प्राधिकार पत्र संख्या के साथ पोतलदान/आपूर्ति दस्तावेज पृष्ठांकित करना होगा। निर्यात/आपूर्ति दस्तावेज (दस्तावेजों) में छूट प्राप्त सामग्री/खपत की गई निविष्टियों का ब्यौरा भी होना चाहिए।

10. पैरा 4.35 (ग) में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(ग) यदि प्राधिकार पत्र धारक जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, तो क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्राधिकार पत्र के पृष्ठांकन के बदले जीएसटी नियमावली के अनुसार क्षेत्राधिकार प्राप्त सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा जाबकर्ता के नामों को प्राप्त करने का विकल्प होगा। ऐसे मामलों में जहाँ प्राधिकार पत्र धारक विनिर्माता निर्यातक जीएसटी अधिनियम के तहत के साथ पंजीकृत नहीं है/पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी से प्राधिकार पत्र में सहायक विनिर्माता के नाम के पृष्ठांकन के पश्चात जाब वर्क की अनुमति होगी। तथापि, प्राधिकार पत्र धारक आयातित मर्दों और निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए पूर्णतया जिम्मेदार होगा।

11. पैरा 4.36 (ख) में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

यदि बैंक गारण्टी/विधिक वचन बद्धता विमुक्त कर दी गयी है, तो अग्रिम प्राधिकार प्रमाणपत्र धारक, जीएसटी अधिनियमों के प्रावधानों के तहत निर्धारित जाब कार्य विनियमन के अनुसार वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अधीन किसी विनिर्माता से शुल्क मुक्त निविष्टियों का संसाधन करा सकता है जिसकी सूचना सीमा शुल्क प्राधिकारी को देनी होगी। तथापि, हस्तान्तरणीय डी एफ आई ए प्रमाणपत्र धारक के मामले में ऐसे प्रतिबन्ध लागू नहीं होंगे।

12. नए पैरा 4.43क को पैरा 4.43 के नीचे जोड़ा गया है जो निम्नानुसार है:

4.43क अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयातित माल का पुनः निर्यात

राजस्व विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार अग्रिम प्राधिकार पत्र स्कीम के तहत आयातित माल के दोषपूर्ण तथा उपयोग हेतु अनुपयुक्त पाए जाने पर, पुनः निर्यात किया जा सकता है। प्राधिकार पत्र धारक को ऐसे दोषपूर्ण माल के पुनः निर्यात से पहले उस क्षेत्रीय प्राधिकारी को सूचित करना होगा, जिसने प्राधिकार पत्र जारी किया है।

13. पैरा 4.44 (ग) में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(ग) ईओडीसी आवेदन की ऑनलाइन फाइलिंग के मामले में तिमाही आधार पर मान्य निर्यात जीएसटी नियमावली के तहत निर्धारित आपूर्तियों के लिए कर बीजक के मामले में निर्यातक डीजीएफटी की आनलाइन प्रणाली में संबंधित फाइल सं./प्राधिकार पत्र सं. तथा संबंधित पोतलदान बिल सं./निर्यात बिल/बीजकों को लिंक करके सभी किए गए निर्यातों को आनलाइन लिंक करेंगे।

14. पैरा 4.47 (घ) में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(घ) ऐसे प्रमाण-पत्र की प्रमाणिकता डीजीएफटी की वेबसाइट (dgft.gov.in) अथवा डीजीएफटी के जोनल कार्यालयों की वेबसाइटों की सहायता से जांची जाएगी। डीजीएफटी के जोनल कार्यालय उनके द्वारा और उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जारी ऐसे ईओडीसी प्रमाण पत्रों का विवरण अपनी अधिकारिक वेबसाइट पर प्रत्येक माह डालेंगे।

15. पैरा 4.50 (च) में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(च) प्राधिकार-पत्र धारक से उक्त दस्तावेजी प्रमाण प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय प्राधिकारी मामले का मोचन करेगा, ईओडीसी/मोचन पत्र पर भुगतान किए गए शुल्क के ब्यौरे को पृष्ठांकित करेगा और पंजीकरण के पत्तन पर अथवा प्राधिकार-पत्र धारक की फैक्ट्री पर क्षेत्राधिकार वाले सीमा-शुल्क के आयुक्त, जैसा भी मामला हो, सीमा-शुल्क प्राधिकारी को की गई वसूली/जमा के विवरण के बारे में सूचित करेगा।

16. पैरा 4.54 में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

4.54 आवेदन-पत्र

(क) 'आयात निर्यात फार्म 4छ' पत्र में आवेदन, आवेदन पत्र में निर्धारित दस्तावेजों के साथ संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ख) इस प्रक्रिया-पुस्तक के पैराग्राफ 4.26, 4.27, 4.28, 4.48, 4.49(ड.) और 4.49(च) तथा 4.52 के प्रावधान डीएफआईए स्कीम के लिए भी लागू होंगे।

(ग) निर्यात के पूरा होने और धनराशि की प्राप्ति के पश्चात् हस्तांतरणीय शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार पत्र जारी करने हेतु अनुरोध संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को निर्यात की तारीख से बारह माह की अवधि के भीतर अथवा निर्यात संबंधी धनराशि के प्राप्त होने की तारीख से छः माह (अथवा आरबीआई द्वारा प्राप्ति हेतु अनुमत अतिरिक्त समय) के भीतर, जो भी बाद में हो, किया जा सकता है।

(घ) प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.02 के अनुसार आवेदक फाइल सं. के सृजन की तारीख से 24 माह के बाद भी आवेदन कर सकता है।

17. पैरा 4.62 में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम धातुओं से बनायी गई वस्तुओं के निर्यात के संदर्भ में इन वस्तुओं के निर्यात के मद्दे मात्रा की हकदारी में अनुमत छीजन/विनिर्माण क्षति सहित निर्यात की मद में स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम की मात्रा होगी। जड़ित आभूषण के मामले में सोना/चांदी/प्लेटिनम धातु की मात्रा का आकलन जुड़ाव के भार को घटाकर किया जाएगा।

18. पैरा 4.64 में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(क) रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र, रत्न एवं आभूषण उत्पादों के निर्यात में प्रयुक्त बहुमूल्य पत्थरों, अर्ध-बहुमूल्य तथा सिन्थेटिक स्टोन और मोतियों के आयात के लिए वैध होगा। इसके साथ-साथ यह प्राधिकार पत्र समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर प्राधिकार पत्र के मूल्य के 5% तक आभूषणों के खाली बक्सों के आयात के लिए भी वैध होगा। जड़ित स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों/वस्तुओं के निर्यात के प्रति जारी रत्न प्रतिपूर्ति प्राधिकार पत्र, समग्र लागत बीमा भाड़ा मूल्य के भीतर प्राधिकार पत्र के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक के पन्ना के अतिरिक्त कट और पालिश किए गए बहुमूल्य/अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के आयात के लिए भी वैध होगा।

(ख) रत्न पुनःपूर्ति प्राधिकार पत्र परिशिष्ट-4च में निर्धारित पुनःपूर्ति दर के अनुसार जारी किया जाएगा तथा जड़े हुए आभूषण के मामले में शेष एफओबी मूल्य संबंधी पुनःपूर्ति का मानदंड परिशिष्ट-4छ के अनुसार होगा।

19 पैरा 4.68(क) में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(क) निर्यातक को जहां कहीं अपेक्षित हो, निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करके

स्वर्ण/ चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों और इसकी वस्तुओं के निर्यात का प्रमाण देना होगा :-

(i) पोतलदान बिल की ई पी प्रति,

- (ii) सीमा-शुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापित जीएसटी नियमावली के तहत यथा निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए कर बीजक,
- (iii) परिशिष्ट 2प में दिए गए प्रपत्र में वसूली का बैंक प्रमाण पत्र/ई-बीआरसी।

20. पैरा 4.73 में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

डाक द्वारा रत्न और आभूषण पार्सल के निर्यात की नीति विदेश व्यापार नीति के पैरा 4.48 दी गयी है। निर्यात के समय, निर्यातक को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे :-

- (i) विदेशी डाकघर में प्रस्तुत किया गया पोतलदान बिल या जीएसटी नियमावली के तहत यथा-निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए कर बीजक,
- (ii) नामित अभिकरणों से प्रमाण पत्र जिसमें वह मूल्य दर्शाया गया हो जिस पर स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम बुक किया गया था या तुरन्त बिक्री आधार पर या ऋण के आधार पर दिया गया था।
- (iii) जीएसटी नियमावली के तहत यथा-निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए कर बीजक की तीन प्रतियाँ।

21. पैरा 4.77(ख) में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(ख) सोना/चाँदी/प्लेटिनम, एलाय, सोना/चाँदी/प्लेटिनम की फाइंडिंग्स और माऊंटिंग्स और सादा अर्द्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों को स्तर धारक/निर्यातक को प्रत्यक्ष पूर्ति के मामले में, मूलभूत सीमा-शुल्क को आयातित सोना/चाँदी/प्लेटिनम, एलॉयस, सोना/चाँदी/प्लेटिनम की फाइंडिंग्स और माऊंटिंग्स और सादा अर्द्ध निर्मित सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों आदि पर लगने वाले सीमा शुल्क के नियम और विनियमनों के अनुसार बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता, सीमा-शुल्क के पास जमा करानी होगी। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगने वाले एकीकृत माल और सेवा कर और मुआवजा उपकर आयात पर अलग से देय होगा।

22. पैरा 4.78(डि)(ii) में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

- (ii) जीएसटी नियमावली के तहत यथा-निर्धारित निर्यात/आपूर्तियों के लिए कर बीजक की तीन प्रतियाँ;

23. पैरा 4.78(ज) में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(ज) उन मदों की अन्तरराष्ट्रीय कीमत में उन पर लगने वाले सीमाशुल्क को जोड़कर उसके बराबर राशि की बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करके निर्यातक अग्रिम रूप से विदेशी क्रेता द्वारा आपूर्तित स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम इत्यादि को प्राप्त कर सकते हैं। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगने वाला एकीकृत माल और सेवा कर और मुआवजा उपकर आयात पर अलग से देय होगा। बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता की राशि तभी वापिस की जाएगी जब निर्यातक नामित एजेन्सी को निर्यात का सबूत प्रस्तुत करेगा तथा निर्यात उत्पाद में मदों की अग्रिम आपूर्ति के उपयोग को ध्यान में रखा जाएगा।

24. पैरा 4.84 (क) में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(क) निर्यातक ऋण आधार पर बहुमूल्य धातु की आवश्यक मात्रा प्राप्त कर सकता है बशर्ते नामित अभिकरण द्वारा निर्धारित राशि हेतु नामित अभिकरणों को सीमा शुल्क हेतु बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत की गई हो। सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम की धारा 3(7) और 3(9) के तहत लगाए जाने योग्य एकीकृत सामान और सेवा कर और मुआवजा उपकर आयात पर अलग से देय होगा। निर्धारित अवधि के भीतर निर्यात करने में असफल रहने पर नामित अभिकरण बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को लागू करेंगे।

25. पैरा 4.85 (ग) में संशोधन किया गया है जिसे निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

(ग) अग्रिम प्राधिकार पत्र धारक सीधे आयात के बदले नामित अभिकरणों से स्वर्ण/चाँदी/ प्लेटिनम को प्राप्त कर सकता है। ऐसे मामले में, नामित अभिकरणों द्वारा स्वर्ण/चाँदी/प्लेटिनम की आपूर्ति की तिथि से 90 दिनों के भीतर

निर्यात दायित्व भरा जाना आवश्यक होगा और नामित अभिकरण प्राधिकार पत्र की विनिमय नियंत्रण प्रति और सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति दोनों सीधे आयात के लिए अवैध कर देगा ।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: प्रक्रिया पुस्तक 2015–2020 के अध्याय–4 में विभिन्न संशोधन किए गए हैं ।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 20th September, 2017

No. 26/2015-2020

Sub: Amendments in Hand Book of Procedures 2015-20 -reg

F. No. 01/94/180/172/AM17/PC-4.—In exercise of powers conferred under Paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade makes the following amendments in Hand Book of Procedures 2015-2020 as under:

1. Para 4.06 is amended to read as under:

4.06 Fixation of Norms

- (i) In case where norms have not been notified or where applicant wants to get the ad-hoc norms fixed before making an application for Advance Authorisation, application in ANF 4B, along with prescribed documents, shall be uploaded online to concerned Norms Committee (NC) in DGFT headquarters for fixation of SION/Adhoc norm. Details of Norms Committees along with products groups dealt by each Norms Committee and respective email addresses for correspondence relating to norms fixation is as follows:

Norms Committees (NC) in DGFT headquarters	For fixation / revision / amendment of norms of Export Products under following ITC HS Chapters	Email addresses for communication with respective Norms Committee
NC-1	81 to 84, 86 to 93	nc1.dgft@nic.in
NC-2	72 to 76, 78 to 80, 85	nc2.dgft@nic.in
NC-3	29, 30	nc3.dgft@nic.in
NC-4	27, 28, 31 to 38, 44 to 49, 68 to 71	nc4.dgft@nic.in
NC-5	41 to 43, 50 to 67	nc5.dgft@nic.in
NC-6	1 to 26, 94 to 98	nc6.dgft@nic.in
NC-7	39, 40	nc7.dgft@nic.in

- (ii) An applicant shall indicate a valid email address for communication purpose and ensure that this email address is active.
- (iii) The decisions of Norms Committees shall be available on the website of DGFT (<http://dgft.gov.in>) periodically and the applicants shall update themselves the status of norms fixation in respect of Authorisation obtained by them.
- (iv) Exporters / EPC shall provide data to the Norms Committee concerned for the fixation of SION/ Adhoc Norms for an export product. Norms Committee shall endeavour to fix SION or adhoc norms on receipt of complete data. Any adhoc norm fixed under this para, on the basis of an application made by an exporter shall be valid for one authorisation for which such application is made and no repeat authorisations shall be issued. However, Norms Committee can specify extended validity period of not more than two years from the date of fixation of such adhoc norms, for grant of further authorisations under such norm.

- (v) Norms Committees shall also function as recommendatory authority for notification of SION and DGFT may notify such norms from time to time.
- (vi) It is mandatory for industry / manufacturers/ EPCs to provide production and consumption data etc. for the past three years, as may be required by DGFT for fixation of SION. Otherwise, applicants shall not be allowed to take benefit of Advance Authorisation scheme for taking repeat Advance Authorisations on self-declared basis. Norms Committee may also seek data from Central Excise (CBEC).
- (vii) Experts may be invited from Scientific and Technological institutions as members of Norms Committee for fixation of Norms.

2. Para 4.10 is amended to read as under:

4.10 Advance Authorisation for applicants with multiple units

- (i) Transfer of any duty free material imported or procured against Advance Authorisation from one unit of a company to another unit for manufacturing purpose shall be done with prior intimation to jurisdictional Customs Authority. Benefit of CENVAT shall not be claimed on such transferred input.
- (ii) Deleted
- (iii) Deleted
- (iv) Deleted
- (v) Imported duty free inputs can be taken from the port / domestic supplier's premises to the factory or the premises of the authorization / co-authorisation holder or the factory of the supporting manufacturer (whose name is endorsed in the authorization or allowed by the Jurisdictional Customs authority). However, such duty free material imported or procured against advance authorization can also be taken from the port directly to the project site of the project authority, subject to furnishing a bond to the customs authority at the port of import and other documents / declaration and other provisions as per Department of Revenue guidelines.

3. Para 4.12 (vii) is amended to read as under:

Wherever an applicant has applied for components on "net-to-net basis with accountability clause" and such cases fall under paragraph 6 of General Note for all Export Products, the same need not be referred to Norms Committee for fixation of norms. However, exporters shall indicate clearly details of such components imported on "net-to-net basis with accountability clause" in the export/supply documents namely Shipping Bills, Bill of Exports, Tax invoice for export/supplies prescribed under the GST rules evidencing that these imported inputs have been exported.

4. Para 4.14 is amended to read as under:

4.14 Application and On-line Inter-Ministerial Consultations for fixation of norms / adhoc norms

- (i) Application filed online by the applicant shall be forwarded electronically to the concerned Technical / Administrative Ministry / Department /Scientific and Technological institutions or any other agency by the respective Norms Committee in the DGFT headquarters within three days.
- (ii) The concerned Technical / Administrative Ministry / Department / Scientific and Technological institutions or any other agency as the case may be, may communicate its views / comments / recommendations within 45 days electronically/online. In case no comments are received within 90 days, Norms Committee may take a view based on the facts available on record.

5. Para 4.16 (iii) is amended to read as under:

In cases where entitlement of the applicant for grant of Advance Authorisation as per paragraph 4.12 was lower than the quantity of input applied by the applicant under Advance Authorisation

and export obligation is completed pending fixation of norms by Norms Committee, entitlement for authorisation as given in paragraph 4.12 may be re-credited upon production of documentary evidence (copies of Shipping bill / bill of export/Tax invoice for supply prescribed under GST rules) showing fulfilment of export obligation in respect of previous authorisations. However, bond waiver / redemption shall not be allowed pending fixation of norms in such cases.

6. Para 4.20 is amended to read as under:

Provisions contained in paragraph 4.49 of Hand Book of Procedures, 2015-20, except sub-paragraph (f), shall be applicable. Regional Authority shall compare the details of Appendix 4-I, duly verified and certified by the jurisdictional Customs Authority, with that of the inputs made/allowed in the authorisation, before allowing redemption or Bond-waiver against individual advance authorization issued for pharmaceutical product(s) manufactured through NI process. As a result of the verification process, in case, it is found that the authorisation holder has consumed lesser quantity of inputs than imported, authorisation holder shall be liable to pay customs duty on unutilized imported material, along with interest thereon as notified by DoR, or effect additional export within the EO period to account for the export of the material remaining unutilized. However, for the Customs duty component, the authorisation holder has also the option to furnish valid duty credit scrip issued under Chapter 3 of FTP

7. Para 4.21 is amended to read as under:

Every Advance Authorisation holder shall maintain a true and proper account of consumption and utilization of duty free imported / domestically procured inputs against each authorisation as prescribed in Appendix 4-I. This record in Appendix 4-I format, duly verified and certified by the jurisdictional Customs Authority, shall be submitted to the concerned Regional Authority at the time of filing application for redemption / bond waiver. Regional Authority shall compare the details of Appendix 4-I, with that of the inputs allowed in the authorisation, before allowing redemption or bond waiver against individual authorization. Such records shall be preserved for a period of at least three years from the date of redemption.

8. Following sub para 4.22(b) (iv) is added below para 4.22 (b)(iii):

(iv) In case an applicant is not able to upload any prescribed document then such documents may be submitted in physical form to the concerned authority.

9. Heading of para 4.27 and Para 4.27(a) is amended to read as under:

4.27 Exports/Supplies in anticipation or subsequent to issue of an Authorisation.

(a) Exports / supplies made from the date of EDI generated file number for an Advance Authorisation, may be accepted towards discharge of EO. Shipping / Supply document(s) should be endorsed with File Number or Authorisation Number to establish co-relation of exports / supplies with Authorisation issued. Export/supply document(s) should also contain details of exempted materials/inputs consumed.

10. Para 4.35 (c) is amended to read as under:

(c). If authorisation holder is registered under GST Act, he has an option of getting names of jobber endorsed by jurisdictional Customs authority as per GST Rules in lieu of Regional Authority's endorsement. In case manufacturer exporter holding authorisation is not registered / not required to be registered under GST Act, job work may be allowed after endorsement of supporting manufacturer's name in the authorisation from RA concerned. However, authorisation holder shall be solely responsible for imported items and fulfilment of EO.

11. Para 4.36 (b) is amended to read as under:

In case BG / LUT has been redeemed, Advance Authorization holder can get duty free inputs processed from any manufacturer under Actual User condition as per job work regulations prescribed in terms of provisions of GST Acts under intimation to the Customs authority. However, such restriction shall not be applicable in case of transferable DFIA holder.

12. New Para 4.43A is inserted below Para 4.43 as under:

4.43A Re-export of goods imported under Advance Authorisation Scheme

Goods imported against Advance Authorisation Scheme, which are found defective or unfit for use, may be re-exported, as per Department of Revenue guidelines. The authorisation holder has to inform the RA who has issued the authorisation before re-export of such defective goods.

13. Para 4.44(c) is amended to read as under:

(c) In case of online filing of EODC application, Exporters shall link all exports on line on DGFT system by linking file number / authorisation number with the relevant shipping bill numbers / bill of exports / invoices in case of deemed exports/Tax invoices for supplies prescribed under GST rules on quarterly basis.

14. Para 4.47 (d) is amended to read as under:

(d) Authenticity of such Certificate may be verified by referring to DGFT website (dgft.gov.in) or from the websites of Zonal offices of DGFT. Zonal offices of DGFT may publish details of such EODC certificates issued by them and by all RAs coming under their jurisdiction on their official websites every month.

15. Para 4.50 (f) is amended to read as under:

(f) On receipt of said documentary evidence from Authorisation holder, Regional Authority shall redeem the case, shall endorse details of duty paid on the EODC/Redemption Letter and inform details of recovery/ deposits made to the Customs Authority at the port of registration or the Commissioner of Customs having jurisdiction over the factory of the Authorisation holder, as the case may be.

16. Para 4.54 is amended to read as under:

4.54 Application

(a) Application in ANF 4G along with documents therein, shall be filed online to concerned Regional Authority.

(b) Provisions of paragraphs 4.26, 4.27, 4.28, 4.48, 4.49(e) & 4.49 (f) and 4.52 of this Handbook of Procedures shall also be applicable for DFIA Scheme.

(c) After completion of exports and realization of proceeds, request for issuance of transferable Duty Free Import Authorisation may be made to concerned Regional Authority within a period of twelve months from the date of export or six months (or additional time allowed by RBI for realization) from the date of realization of export proceeds, whichever is later.

(d) Applicant shall be allowed to file application beyond 24 months from the date of generation of file number as per paragraph 9.02 of Hand Book of Procedures.

17. Para 4.62 is amended to read as under:

Entitlement of quantity of gold / silver / platinum against the export of articles made out of these metals shall be quantity of gold / silver / platinum in item of export plus admissible wastage / manufacturing loss. In the case of Studded Jewellery, the calculation of the quantum of gold/silver/platinum metal shall be done excluding the weight of studding.

18. Para 4.64 is amended to read as under:

(a) Gem REP Authorisations shall be valid for import of precious stones, semi-precious and synthetic stones and pearls used in export of Gems and Jewellery products. In addition, Authorisation shall also be valid for import of empty jewellery boxes up to 5% of value of Authorisation within its overall CIF value. Gem REP Authorisations issued against export of studded gold / silver / platinum jewellery articles, shall also be valid for import of cut and polished precious / semi- precious stones other than emerald up to 10% of CIF value of Authorisation within its overall CIF value.

(b) Gem REP Authorisation will be as per the replenishment rate prescribed in Appendix -4F and the scale of replenishment on the remaining FOB value in the case of studded jewellery shall be as given in Appendix-4G.

19. Para 4.68(a) is amended to read as under:

(a) Exporter has to furnish the proof of exports, wherever required for export of gold / silver / platinum jewellery and articles thereof, by furnishing following documents:

- (i) E.P copy of the shipping bill;
- (ii) Customs attested Tax invoice for export/supplies as prescribed under GST rules ;
- (iii) Bank certificate/e-BRC of realisation in Appendix 2U.

20. Para 4.73 is amended to read as under:

Policy for export of gems and jewellery parcel by post is in paragraph 4.48 of FTP. At the time of exports, exporter shall submit following documents:

- (i) Shipping bills or Tax invoice for export/supplies as prescribed under GST rules presented at foreign Post Office;
- (ii) Certificate from nominated agencies indicating price at which gold/ silver/platinum was booked or given on outright sale basis or loan basis;
- (iii) Three copies of Tax invoices for export/supplies as prescribed under GST rules .

21. Para 4.77 (b) is amended to read as under:

(b) In case of direct supply of gold/silver/platinum, alloys, findings and mountings of gold/ silver/ platinum and plain semi-finished gold/silver/platinum jewellery to status holder/ exporter, Status Holder/exporter shall furnish a Bank Guarantee/LUT, as per Customs Rules and regulations to Customs equivalent to Basic Customs Duty leviable on imported gold/ silver/ platinum, alloys, findings and mountings of gold/ silver/ platinum and plain semi-finished gold/ silver/ platinum jewellery etc. Integrated Goods and Services tax and Compensation Cess leviable under Section 3(7) and 3(9) of Customs Tariff Act shall be payable separately on imports.

22. Para 4.78(e)(ii) is amended to read as under:

(ii) Three copies of Tax invoices for export/supplies as prescribed under GST rules;

23. Para 4.78 (h) is amended to read as under:

(h) Exporter may also obtain, in advance, gold/ silver/ platinum etc. supplied by foreign buyer by furnishing a BG /LUT for an amount equal to international price of such items plus basic customs duty payable thereon. Integrated Goods and Services tax and Compensation Cess leviable under Section 3(7) and 3(9) of Customs Tariff Act shall be payable separately on imports. BG /LUT shall be redeemed only when the exporter has furnished proof of exports to nominated agency and accounted for the use of items supplied in advance in export product.

24. Para 4.84(a) is amended to read as under:

(a) Exporter may obtain required quantity of precious metal on loan basis subject to furnishing of BG / LUT, for customs duty to nominated agencies for an amount as may be prescribed by nominated agencies. Integrated Goods and Services tax and Compensation Cess leviable under Section 3(7) and 3(9) of Customs Tariff Act shall be payable separately on imports. On failure to effect exports within the period prescribed, the nominated agencies shall enforce the BG / LUT.

25. Para 4.85(c) is amended to read as under:

(c) Advance Authorisation holder may obtain gold /silver / platinum from nominated agencies in lieu of direct imports. In such a case, EO will be required to be fulfilled within 90 days from date of supply of Gold/Silver/Platinum by nominated agency and the nominated agency shall also

make, both exchange control copy and customs purpose copy of Authorisation invalid for direct imports.

Effect of this Public Notice:

Various amendments are made in Chapter-4 of Hand Book of Procedures 2015-2020.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade